बनते हुए, जनता को सस्ता कपड़ा नहीं मिलता है और इस में बहुत घोटाला होता है। मैं जानना चाहता हूं कि सही दाम पर जनता को कपड़ा मिले, इस के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी ?

SHRI PRANAB MUKHERJEE : So far as distribution is concerned, unfortunately, I am not in a position to say anything, as I told you ; it is produced and after that, it is distributed through the State agencies and cooperative sector.

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान

*83. **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री राज नाथ सोनकर शास्त्री :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मूल्य सूचकांक निरंतर बढ़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी नवीनतम स्थिति क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि मूल्य सूचकांक में हुई इस वृद्धि के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी बढ़ा दिया गया है ;

(घ) यदि हां, तो महंगाई भत्ते की कितनी किस्तें सरकार द्वारा देय हो गई हैं; और

(ङ) सरकार का विचार कब तक उनका भुगतान करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, हां।

(ख) जून 1981 के लिए लेबर ब्यूरो, शिमला से प्राप्त नवीनतम सूचकांक 439 हैं जून, 1981 सहित पिछले 12 महीने का सूचकांक औसत 413.84 है।

(ग) से (ङ) : केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की पिछली किस्त उस समय मंजूर की गई थी जब 12 महीने का सूचकांक औसत 392 हो गया था। मार्च, 1981 तथा मई, 1981 के अन्त में सूचकांक औसत में 8 अंकों की वृद्धि होने के परिणामस्वरूप 1-4-81 तथा 1-6-81 से महंगाई भत्ते की दो और किस्तें विचार किये जाने योग्य हो गई हैं। इन किस्तों की अदायगी का प्रश्न सरकार के ध्यान में है। चूंकि ऐसी अदायगी पर, देश की आर्थिक स्थिति के साथ-साथ विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सावधानी से विचार किया जाना होता है, इसलिए इस मामले में निर्णय लेने में स्वभावत: कुछ समय लग सकता है।

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष जी, यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय : आपने किया है, इसलिए मानना ही पड़ेगा।

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष जी, कीमतें शैतान की आंत की तरह बढ़ती जा रही हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह नया मुहावरा आज निकाला है आप ने।

श्री रामावतार शास्त्री : आप सुन लीजिए। मंत्री जी ने जो बयान दिया है, उसके अनुसार जून, 1981 में सूचकांक 439 आ गया और 12 महीने का औसत सूचकांक 413.84 था। इस से अन्दाजा लगाया जा सकता है कि कीमतें कितनी बढ़ती जा रही हैं। मेरे पास बहुत सारी फीगर्स हैं लेकिन वक्त कम है, इसलिए मैं उन को नहीं बताना चाहता, पर यह कहना चाहता हूं कि आप हर साल सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की किस्तें देते जा रहे हैं। सन् 1980

में 5 किश्त उन की हुईं और उन में से 4 तो आप ने सन् 1980 में दी और पांचवीं किश्त आप ने 1981 में दीं। अब इस साल अभी तक तीन किश्तें ड्यू हो चुकी है, जो पिछली बकाया है और उन में से आप एक दे चुके हैं 10-7-81 को और आप के मुताबिक दो अभी बकाया हैं, एक 1-4-81 से और दूसरी 1-6-81 से। ये महगाई भत्ते की किश्तें उनको बकाया पड़ी हुई है और महगाई आप रोक नही पा रहे है उन को ये किश्तें दे भी नही रहे है।

पहली बात तो मैं यह जानना चाहूंगा कि जो द्विपक्षीय समझौता कर्मचारियों और सरकार के बीच में हुआ है, वह द्विपक्षीय समझौता क्या है और जो दो किश्तें बाकी हैं, उन को देने में टाल-मटोल की नीति क्यों बर्ती जा रही है। हम सफाई के साथ यह जानना चाहते है कि इन दोनों किश्तों को देने के लिए क्या आप कोई निश्चित तारीख बताएंगे ?

अध्यक्ष महोदय : जुबान की सफाई से सुनना चाहते हे या हाथ की सफाई से ?

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का जो विषय है वह सचमुच में महत्वपूर्ण विषय है और जब शास्त्री जी ने यह प्रश्न पूछा है तो यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर भी माननीय सदस्य महोदय ने जो जानकारी चाही है वह सफाई के साथ नहीं, बल्कि जो जानकारी मेरे पास है उसके आधार पर मैं दे रहा हूं।

इस प्रश्न पर हमें व्यापकता के साथ विचार करना है। अगर वे मेरे उत्तर को सहानुभूति के साथ देखेंगे तो इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि यह डियरनेस अलाउंस का प्रश्न आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसका हमारे देश के बजट पर कितना प्रभाव पड़ता है, उसके आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जब एक किश्त सरकार कर्मचारियों को देने का निर्णय करती है तो उसका प्रभाव बजट पर 62 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष पड़ता है। इसके अलावा पांच करोड़ रुपये पेंशनर्स को भी देने पड़ते है। इस तरह से प्रतिवर्ष 67 करोड़ रुपये का हमारे बजट पर प्रभाव पड़ता है। अभी तक जो 24 अतिरिक्त किश्तें दी जा चुकी हैं उनका 1336 करोड़ रुपये का हमारे बजट पर प्रभाव पड़ा है। इतना बड़ा प्रभाव आर्थिक दृष्टि से हमारे बजट पर पड़ता है तो शासन के लिए यह सोचना जरूरी हो जाता है कि वह उसके तमाम पहलुओं पर विचार कर के ही भत्ते को देने की व्यवस्था करे। शासन के लिए यह भी सोचने की बात है कि हमारी आर्थिक स्थिति के ऊपर भी और तत्काल महंगाई के ऊपर भी इसका किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा ? इस सारी स्थिति पर विचार करना जरूरी है।

मैं माननीय शास्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्रीय शासन अपने कर्मचारियों के प्रति पूरी सहानुभूति रखता है और वह इस बात से भी वाकफियत रखता है कि महंगाई बढ़ने से उन्हें कुछ दिक्कतें है। उन दिक्कतों को ध्यान में रख कर इस बारे में कोई निर्णय लेने में सरकार कोई विलम्ब नहीं करेगी।

श्री रामावतार शास्त्री : मैंने यह पूछा था कि कर्मचारियों के साथ, या उनके प्रतिनिधियों के साथ इस मामले में आपने क्या समझौता किया था। उसी से पता चलेगा कि आप क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं ?

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : कर्मचारियों और शासन के प्रतिनिधियों को मिला कर एक ज्वाएंट कंसलटेटिव मशीनरी मौजूद है और उस ज्वाएंट कंसलटेटिव मशीनरी की एक कमेटी है। उस कमेटी के सामने स्टाफ की तरफ से ये मांगें उठायी गयी थीं। ये मांगे विचारणीय हैं। उन पर विचार किया जा रहा है, अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। इसीलिए मैंने यह जानकारी नहीं दी है। यथा-योग्य निर्णय हो जाने के बाद, उसकी सूचना दी जा सकेगी।

श्री रामावतार शास्त्री : सरकार जो भत्ता देती है, उसके लिए जे० सी० एम० में कोई सिद्धांत तय किये होंगे। मैं उन सिद्धांतों को जानना चाहता हूं तभी तो मैं आप को पकड़ सकूंगा कि आप उन सिद्धांतों को लागू कर रहे हैं या तोड़ रहे हैं। मैंने यह पूछा है कि आपने कोई सिद्धांत तय किये है या नहीं ? वे सिद्धांत बताइये।

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : शास्त्री जी अफसोस है कि जो सही बात मैंने आपके सामने रखी उसे आपने समझने की कोशिश नहीं की। इसीलिए वे उलझन की बात कर रहे हैं। अगर हम अब सिद्धांतों पर विचार करेंगे तो काफी डिस्कशन, काफी वाद-विवाद की आवश्यकता पड़ेगी। यह प्रश्नकाल है और इसका समय मूल्यवान है। इस संक्षिप्त और मूल्यवान समय में मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता।

श्री रामावतार शास्त्री : अभी आपने बताया कि महंगाई भत्ते की किस्त को देने के साथ आर्थिक स्थिति और दूसरे सवाल जुड़े हुए हैं और आपको इन पर विचार करना पड़ता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या महंगाई भत्ता देने के कारण वे सवाल उठ खड़े होते हैं या आपकी सरकार की पूंजीपति परस्त नीति इस संकट के लिए जवाबदेह है ? आप जो इतने पैसे दे चुके हैं, जिनका कि आपने जिक्र किया, क्या इनकी वजह से आपका आर्थिक संकट विद्यमान है या हमारी समझ में आपकी पूंजीवादी नीति ही इस संकट को खड़ा करती है ? इस बारे में बताइये। कोई संकट वाली बात नहीं है—आर्थिक विषमता जरूर है और डियरनेस अलाउंस देने से 67 करोड़ रुपया खर्च में जुड़ जाता है, इसका परिस्थिति पर क्या असर पड़ेगा, इस पर विचार किया जाना आवश्यक है, लेकिन मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि दोनों सदनों में महंगाई के प्रश्न पर विचार करने के लिए माननीय वित्त मन्त्री जी ने प्रस्ताव रखा है और वह प्रस्ताव स्वीकार हो गया है। इसके अलावा आज प्रश्न संख्या 86 और 90, ये दोनों प्रश्न प्राइस-राइज़ के बारे में हैं—उस समय अगर इन प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय इस तरह का गोल-मोल जवाब दिया गया है, हम स्पष्ट जवाब चाहते हैं कि किस तारीख तक देंगे ...।

अध्यक्ष महोदय : नाट अलाउड। उन्होंने जवाब दे दिया है।

Don't take all the time, Mr. Shastri Please don't monopolise.

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : माननीय मन्त्री जी ने एक शास्त्री जी का जवाब दिया है, अब दूसरा शास्त्री मैं खड़ा हूं।

अध्यक्ष महोदय : 11 शास्त्री हो गए हैं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मान्यवर मन्त्री जी ने शास्त्री जी के जवाब में जो खाका खींचा और कहा कि समय कम है और मूल्यवान समय है—तो वस्तुतः मूल्यवान समय मूल्यवान प्रश्न ही पूछा जा रहा हे, जिस पर सारे देश की आंखें लगी हुई हैं···।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिए।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूँ। पिछले एक वर्ष में 20 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक भाव बढ़ गए है और मुद्रास्फीति की वार्षिक दर भी 20 प्रतिशत की रेखा पार कर गई है और वर्ष की समाप्ति तक 25 प्रतिशत तक पहुँच जाने की आशा है—यह जानकारी आपने ही दी है। इस प्रकार लगातार समय-समय पर वेतन-वृद्धि होती है, फिर महंगाई बढ़ती है और फिर वेतन-वृद्धि होती है, तो यह चक्र कब तक चलता रहेगा। क्या इसका कोई स्थायी हल सरकार ढूंढने जा रही है ? इसके अलावा जो दो किश्तें बकाया हैं, उनके बारे मे मन्त्री जी ने बड़ा भ्रमात्मक उत्तर दिया है। मन्त्री जी ने राज्यसभा में कहा था कि अप्रैल और जून की दो किश्ते बाकी है···।

अध्यक्ष महोदय : वे तो अब भी कह रहे है। इसका उत्तर आ चुका है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : ठीक है, यह जो महंगाई और वेतन-वृद्धि का चक्र चल रहा है, इसको रोकने के लिए सरकार स्थायी रूप से क्या करने जा रही है ?

श्री सिवाई सिंह सिसोदिया : मै शास्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं यह प्रश्न कर्मचारियों के महगाई-भत्ते से सम्बन्धित है। प्राइस-राइज़, इन्फ्लेशन या और दूसरे बहुत से प्रश्नों का इससे सम्बन्ध नही है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : एक दूसरे से संबंधित प्रश्न हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस सवाल पर फाईनेंस मिनिस्टर ने एक बयान दिया है जिस पर डिस्कशन होनी है। इस पर बहुत ज्यादा डिस्कशन की जरूरत है। डिस्कशन आ रही है।

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : आपने उचित ही निदेश दिया है कि इसका जवाब दिया जा चुका है। उसको दोहराने की आवश्यकता नही ···।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : यह चक्र कब तक चलता रहेगा ? सरकार इस को रोकने के लिए क्या उपाय कर रही है।

अध्यक्ष महोदय : डिस्कशन आ रहा है इस पर।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : कब तक महंगाई इसी तरह से बढ़ती रहेगी और बकाया राशि के लिए कब तक कर्मचारी इस तरह से लड़ते रहेंगे ? स्थायी रूप से इस महंगाई को रोकने के लिए आपने क्या प्रबन्ध किया है ?

अध्यक्ष महोदय : यह चीज डिस्कशन मे आएगी।

श्री सत्य नारायण जटिया : महंगाई भत्ते का सवाल प्राइस इन्डेक्स के साथ जुड़ा हुआ है। पिछले एक साल में 25 प्वाइन्ट महंगाई बढ़ी है। जब महंगाई भत्ते का सवाल प्राइस इन्डेक्स के साथ जुड़ा हुआ है तो जब वह लिमिट आ जाती है जिस पर उनका महंगाई भत्ता बढ़ना चाहिए तो उसी वक्त मंहगाई भत्ते को बढ़ा क्यो नही दिया जाता है ? तभी महंगाई भत्ता आप क्यो नही बढ़ा देते हैं ? ऐसा न करने का कारण क्या है ?

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : स्टाफ की तरफ से यह मांग उठाई गई है। लेकिन ऐसा कोई एग्रीमेंट जे० सी० एम० से नहीं है कि जैसे ही महंगाई बढ़े आटोमैटिकली इन्स्टालमेंट दे दी जाए। ऐसी स्थिति पैदा होने पर शासन उस पर विचार करता है और निर्णय लेने पर उस पर अमल किया जाता है। यह चीज आटोमैटिक नहीं है।

एक माननीय सदस्य : इस तरफ भी देखें।

अध्यक्ष महोदय : पढ़ने की आंख थोड़ी बहुत खराब हैं लेकिन दूर की बहुत ठीक हैं।

श्री डी० पी० यादव : यह देश का दुर्भाग्य है कि सब से निरीह प्राणी संसद सदस्य होता है। महंगाई कितनी भी बढ़ जाए उस का एक पैसा नहीं बढ़ता है। मंहगाई को लेकर बहुत हल्ला अखबारों में होता है लेकिन संसद सदस्य को यह भत्ता नहीं मिलता है। मैं पच्चीस हजार स्क्वेयर किलोमीटर का दौरा करूं, अपने क्षेत्र से यहां आऊं, एक दर्जन आदमी मेरे आएं, उनको खाना खिलाऊं, फिर वापिस जाने के लिए किराया दूं··· ·· (इंटरप्शंज)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपका अनुमोदन कर रहा हूं। हाउस को आपका धन्यवाद करना चाहिये। यहां बोलते हों, या न बोलते हों लेकिन मेरे पास आकर जरूर बोलने है।

श्री डी० पी० यादव : हमारा जो उत्तरदायित्व है, जो रिसपांसिबलिटीज हैं, जो आब्लीगैशंज है, कांस्टीट्यूएसी के प्रति, परिवार के प्रति, तमाम लोगों के प्रति, उसके अनुरूप हमारी तनख्वाह बढ़ेगी या नहीं हमें मंहगाई भत्ता मिला करेगा या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत परटिनेंट क्वैश्चन है।

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : माननीय सदस्य को अच्छी तरह पता है कि प्रश्न केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते के भुगतान के बारे में है। जो प्रश्न उन्होंने उठाया है उसके गुण दोष के बारे में मैं आज कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। सम्बन्धित मंत्री महोदय से वह पूछेंगे तो इसका उत्तर उनको प्राप्त हो जायेगा।

श्री विलास मुत्तेमवार : अध्यक्ष जी, मंत्री महोदय सहमत हैं कि नहीं, यह तो कह सकते हैं।

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI R. VENKATARAMAN) ; This concerns the Minister of Parliamentary Affairs.

MR. SPEAKER : I would request the Finance Minister not to pass the buck.

SHRI R. VENKATARAMAN : If the Minister of Parliamentary Affairs makes a recommendation, it will be given due consideration.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: When the DA is due to them and you do not give it, how can you give due consideration to this ?

SHRI SUNIL MAITRA : It is very unfortunate that just now we have seen the Hon. Minister linking up the question of DA to Government employees with the question of inflation in this country and other economic policies of the Government. In June the price index was 439. But the all India average for the last 12 months was 413.84 or 414. So, by this month, in terms of dearness allowance actually three instalments have become due. The Minister has stateted that Rs. 1,084

crores have been paid to the Central Government employees by way of dearness allowance. But he has not mentioned whether this figure is for the period from 1960, 1952 or even earlier than that. So, in that way he is trying to mislead the public. Therefore, I want to know whether the Minister seriously believes that the payment of DA to the Government employees will aggravate the inflationary spiral. as my friend was saying, which I do not subscribe to, because of the simple fact.....

AN HON. MEMBER : What is the question ?

SHRI SUNIL MAITRA : This is the question. Out of the total national income of this country for the organised sector, only 18 per cent is accounted for by salaries and wages Therfore, if you pay dearness allowance to a fraction of this 18 per cent, it does not have any repercussion whatsoever, so far as your inflationary situation is concerned. From this point of view, will the Hon. Minister please reconsider the situation and pass orders immediately to pay the dearness allowance, which has already become over-due, to the Government employees ?

SHRI R. VENKATARAMAN : The Hon. Member has advanced his argument in favour of giving dearness allowance. The point which my colleague made was that we take into account its effect on the general price level and on the budgetary situation. Having taken all factors into consideration, we decide as to when we should give the dearness allowance. We have not so far denied the right. What we have said is that we are taking all these factors into consideration and, as and when our finances permit, our circumstances permit, we are giving them dearness allowance. We have to consider so many things. This is the position. Unnecessarily, the other side wants to make it appear that they are the champions of the Government servants.

SHRI SUNIL MAITRA : Certainly we are.

SHRI R. VENKATARAMAN : Please hear me. On the contrary, in the Joint Consultative Machinery they are negotiating and discussing informally with the Secretaries and departmental heads in an atmosphere of complete confidence.

SHRI JANARDHAN POOJARY : May I know whether Government are thinking of impounding 50 per cent of the extra dearness allowance and disbursing only 50 per cent ?

SHRI R. VENKATARAMAN : Sir, this is a suggestion which has been floated, but the Government have not taken any firm decision on this matter. Government will like to discuss this not with the other people, but with the people in the Services through the JCM.

MR. SPEAKER : Mr. Mani Ram Bagri,

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : What about discussions with other people ?

MR. SPEAKER : No discussion, Mr. Mani Ram Bagri. (*Interruptions*)

SHRI R. VENKATARAMAN : I repeat, people other than Government servants.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : But we also represent their interests.

AN HON. MEMBER : No, you do not.

SHRI SATRASADHAN CHAKRABORTY : This is your opinion. (*Interruptions*)

श्री मनी राम बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि इस देश के अन्दर एक तो कलम घिसाऊ मजदूर है, कलम पकड़ाऊ मजदूर हैं यानी 1000 से ऊपर वाले और 1000 व 500 रुपये के बीच वाले, और एक हैं केन्द्र के ही अपने जिस्म की मेहनत करने वाले मजदूर चाहे उनको कम पैसा मिल रहा है, सब से ज्यादा हिन्दुस्तान के संगठित लोगों को चाहे मेहनत कम हो, मजदूरी का उजराना मिल रहा है, निस्बतन इसके कि जो टैम्पोरेरी हैं, आरजी हैं, डेलीवेजेज के हैं या फावड़े का मजदूर है और चपरासी वगैरा जो मजदूर हैं, उनको कम मिल रहा है। मैं केन्द्र की ही बात कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : हिन्दुस्तान का खजाना लुट रहा है।

श्री मनीराम बागड़ी : क्या एक बुनियादी सवाल की तरफ केन्द्रीय मंत्रिमण्डल या केन्द्रीय सरकार सोचेगी कि असंगठित मजदूर चाहे वह खेत का मजदूर हो, चाहे बन्धुआ मजदूर हो, चाहे आपके राष्ट्रपति भवन का मजदूर हो, चाहे दिल्ली का भंगी हो उसके मुकाबले में कलम घिसाऊ और सैक्रेटैरिएट तक कहलाने वाले मजदूरों के बीच में जो अन्तर है वह कम से कम होना चाहिये। जीवन जिस पर व्यतीत होता है उतनी व्यवस्था देने की क्या बात पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है वह काफी महत्वपूर्ण है और केन्द्रीय शासन के सामने न सिर्फ संगठित कर्मचारी ही है जो कि कार्यालय में काम करते हैं, कारखाने में काम करते हैं, उनके प्रति ही मन में चिन्ता नहीं है बल्कि उन तमाम आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोगों के प्रति पूरी सहानुभूति है और चिन्ता व्याप्त है और एक निश्चित कार्यक्रम केन्द्रीय सरकार के सामने है। उनके आर्थिक उत्थान के लिए भी सही कदम उठाये जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह पूछ रहा हूँ कि क्या अनुपात बना रहे है। जो खेत मजदूर है और जो दूसरे सरकारी महकमों के लोग हैं, इनके बीच में कोई अनुपात है या नहीं ? Is there any co-relation between their wages or not ? What are your thinking about that ?

SHRI R. VENKATARAMAN : Not that I know of.

SHRI XAVIER ARAKAL : Sir, the Hon. Minister has given the answer from a wider angle as far as the unorganised labour is concerned. The Hon. Speaker has just now pointed out the question of farm labourers. We are debating the rights of 1 6 per cent of the labour force. (*Interruptions*). 98 per cent of the population do not have any such rights. Where is the distributive justice ?

Therefore, I would like to ask the Government :

(a) What the Government is proposing to do with the dearness allowance of the organised sector and the unorganised sector and (b) Does the Government propose to convert it into compulsory deposit or something like that ?

Mr. SPEAKER : As Hon. Member of this House, everybody has his own opinion.

(Interruptions)

Mr. SPEAKER : I am the guardian of the democratic principles of this nation.

SHRI SAWAI SINGH SISODIA : Our party is committed for the betterment of all the weaker sections of society ; and, therefore, under the leadership of Shrimati Indira Gandhi we will not leave any stone unturned to better the lot of the weaker sections of society.

Continuance of Cotton Monopoly Purchases

*84. SHRI UTTAM RATHOD : Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Maharashtra Government wants to continue cotton monopoly purchases for another ten years ;

(b) whether it is a fact that cultivators all over Maharashtra have been convinced of the benefit of this scheme and want it to be continued; and

(c) what is the reaction of the Central Government in the matter ?

THE MIMISTER OF COMMERCE AND STEEL AND MINES (SHRI PRANAB MUKHERJEE) : (a) Yes, Sir.

(b) There is a mixed reaction to the continuance of cotton monopoly procurement scheme of Maharashtra. Representations have been received in this Ministry from Cotton growers of Maharashtra for and against the continuance of the scheme.

(c) After due consideration, the Central Government have given its consent for extension of the scheme for a further period of one year from 30th June, 1981. It has been proposed to review the working of the scheme towards the end of 1981-82 cotton season.

SHRI UTTAM RATHOD : Recently, the Government of Maharashtra has come out with an ordinance with the consent of the Central Government which envisages the procurement, processing and marketing Act of 1971 i.e. cotton monopoly purchase. It also envisages a Committee, known as Cotton Co-ordination Committee with four members from the Central Government and four members from the State Government. This particular Committee is expected to fix the guaranteed price of raw cotton and also the sale price of the cotton procured and ginned by the agencies. I would like to know :

1. Will the guaranteed price be decided only as per A.P.C's recommendation or will they go according to the prevalent market price?

2. Will the sale price also be fixed taking into consideration the market price or will this tactics be used to bring down the market price ?

3. There are ...

MR. SPEAKER : Only one supplementary. Please do not make it a catologue of supplementaries.

SHRI UTTAM RATHOD : There are four representatives of the Central Government and four representatives of the State Government. If there is any dispute, may I know how and who will decide this issue?

SHRI PRANAB MUKHERJEE: So far as the determination of the guaranteed price is concerned, this is not the first time that we are having this type of scheme. There has been a system which has been prevalent for quite some time. I would not like to pass on the judgement of the Committee. Let them do it. In regard to the determination of the sale, they will have to take